दैनिक जागरण

अपेक्षाओं का बोझ जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है

ईवीएम का रोना

आम चुनावों के नतीजे आने के ठीक पहले इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर जो हल्ला-हंगामा मचाया जा रहा वह राजनीतिक शरारत का हिस्सा ही है, इसकी पुष्टि उन शिकायतों से होती है जो झूठी पाई गईं। चूंकि यह हल्ला-हंगामा एक्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद मचा इसलिए यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि विपक्ष अपनी संभावित हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की पेशबंदी कर रहा है। क्या यह अजीब नहीं कि विपक्षी दल उन एक्जिट पोल के आंकड़ों से सशंकित हो रहे हैं जिनका ईवीएम से कोई लेना-देना ही नहीं? इस पर भी गौर करें कि वे एक्जिट पोल को खारिज भी कर रहे हैं और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका भी जता रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम को संदिग्ध बताने का अभियान छेड़ा गया हो। बीते तीन-चार सालों से यही हो रहा है और इसके बावजूद हो रहा है कि इस दौरान इन्हीं दलों ने पंजाब, केरल के साथ-साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है। इन राज्यों में चुनाव जीतने के पहले दिल्ली एवं बिहार के नतीजे भी ईवीएम से ही निकले थे और कई लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के उपचुनावों के भी। विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर संदेह जताने के साथ ही निर्वाचन आयोग पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं वे भी उनकी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा जान पड़ता है। ये वही दल हैं जो संस्थाओं के क्षरण का भी रोना रो रहे हैं। बेहतर हो कि वे यह देखें कि निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा से कौन खेल रहा है?

हैरत केवल इस पर नहीं कि विपक्षी दल ईवीएम को लेकर नित-नए संदेह खड़े कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी है कि वे मतपत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। क्या वे यह नहीं जानते कि मतपत्र के जमाने में किस तरह धांधली होती थी? वे भूल गए हों तो कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों की याद करें, जब मतपत्र लूटने के साथ मतपेटियों को तालाबों और कुओं में फेंक दिया गया था। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मतदान बाद पर्चियों का सौ प्रतिशत मिलान ईवीएम से कराने की मांग की गई थी। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दलों की 50 फीसद ईवीएम का मिलान मतदान बाद पर्चियों से कराने की मांग खारिज कर चुका था तब फिर फालतू की इस याचिका को क्यों सुना गया? ईवीएम पर बेवजह के शक और फालतू की याचिकाओं को महत्व देना ठीक नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का लक्ष्य इन मशीनों पर सवाल उठाते रहना ही है। खेद की बात यह है कि ईवीएम के खिलाफ झूठी जानकारी के प्रसार में मीडिया का भी एक हिस्सा लिप्त दिखता है। निर्वाचन आयोग के लिए उचित यही है कि वह चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाले जायज सवालों का समाधान करने के साथ ही यह भी देखे कि इस प्रक्रिया को और सुगम एवं छोटा कैसे बनाया जाए, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी जटिल और लंबी चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं।

संवेदनशीलता जरूरी

झारखंड में फुल लोड के बावजूद बिजली की कमी से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में भी ऐसे ही हालात हैं। बिजली संकट का सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ता है और इस कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इतनी गर्मी में लोगों को पंखा चलाने को नहीं मिले और पानी की भी समस्या हो तो यह समझा जा सकता है कि परेशानी किस स्तर की है और इसके निदान के लिए क्या करना होगा। आवश्यक है कि व्यवस्था संवेदनशील हो और समय पर समस्याओं का निदान किया जा सके। इससे नियमित बिजली बिल भुगतान करनेवाले उपभोक्ताओं को कम से कम संतुष्टि मिलेगी। गर्मी के दिनों में बिजली का लोड बढ़ना सामान्य सी बात है और एक बार फिर राज्य में ऐसे ही हालात हैं, लेकिन बिजली की उपलब्धता के बावजूद बड़े पैमाने पर कटौती से आम लोगों को परेशानी हो रही है। डीवीसी कमांड एरिया में कटौती और लोड शेडिंग का असर रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, लोहरदगा आदि जिलों में देखने को मिल रहा है। अधिकारी फॉल्ट होने की बात करते हैं, लेकिन इसे सुधारने के लिए उन्हें कम मौके नहीं मिले होते। सभी यह महसूस करते हैं कि साल भर बिजली दुरुस्त करने के लिए नियमित तौर पर बिजली कटौती होती है और व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर दिनभर बिजली काटने के बावजूद हालात का नहीं सुधरना घातक है। इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की संवेदनहीनता है। व्यवस्था संवेदनशील होकर काम करे तो इस तरह की परेशानियों का समय से उपाय हो सकता है, खासकर लोकल फॉल्ट जैसे मुद्दों का। अब जरा शहरों का हाल देखें। जामताड़ा, गोड्डा आदि शहरों में आधे दिन बिजली नहीं रहती। बड़े शहरों में कुल मिलाकर ऐसा ही हाल है। रांची, धनबाद, कोडरमा, बोकारो आदि शहरों में भी कटौती से आम जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जमीनी स्थिति का आकलन कर बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने की कवायद करें। सिर्फ आंकड़े गिनाने से बात नहीं बनेगी। इससे राज्य की छवि भी जुड़ी हुई है। बिजली की उपलब्धता अगर मांग के अनुरूप है तो वह धरातल पर भी नजर आना चाहिए। बेहतर यही होगा कि मानसून प्रभावी होने से पहले मरम्मत के काम युद्धस्तर पर निपटाए जाएं।

तेज होती व्यापार युद्ध की तपिश

हर्ष वी पंत

अमेरिका-चीन के बीच खींचतान में भारत को ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे न केवल उसके तात्कालिक हित सुरक्षित रहें, बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता को बल भी मिले

व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में चीन की दिग्गज तकनीकी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप के इस आदेश के बाद हुआवे के लिए अमेरिकी बाजार में परिचालन संभव नहीं होगा। ट्रंप की सख्ती के पीछे यह वजह बताई जा रही है कि चीन अपनी इस दिग्गज कंपनी के माध्यम से व्यापक स्तर पर जासूसी कराने के अलावा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक अपनी पहुंच बना सकता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी और 70 अन्य कंपनियों को अपनी तथाकथित 'एंटाइटी लिस्ट' में डाल दिया है। इसके चलते चीनी कंपनी अमेरिकी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अमेरिकी कंपनियों से किसी तरह की तकनीकी या कलपुर्जों की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके अमेरिकी कंपनियों को हिदायत दी है कि वे ऐसी कंपनियों से दूरसंचार उपकरण न खरीदें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। गूगल और क्वालकॉम जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियां हुआवे के साथ तकनीकी साझेदारी न करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के आदेश में कहीं भी हुआवे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन निशाना स्पष्ट रूप से वही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है। यह ताजा प्रकरण व्यापार युद्ध की उस आग में और घी डालने का ही काम करेगा। इस ट्रेड वॉर में तकनीक भी लड़ाई का एक प्रमुख अखाड़ा है तो यह प्रकरण न केवल द्विपक्षीय रिश्तों की प्रकृति, बल्कि निकट भविष्य में वैश्विक राजनीति एवं आर्थिकी पर भी अपना असर डालेगा।

स्वाभाविक रूप से हुआवे ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार उसके व्यापार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसके व्यापार में बाधा डालने से अमेरिका अपने देश में अगली पीढ़ी के उन्नत मोबाइल नेटवर्क को विकसित करने में पीछे रह जाएगा। बीजिंग के अनुसार अमेरिका ने कुछ चुनिंदा चीनी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी नियम-कानूनों का सहारा लिया है ताकि उनके सामान्य एवं कानून के दायरे में संचालित कारोबार पर प्रहार किया जा सके और चीन सरकार अपनी कंपनियों के वैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए किसी भी कोशिश से पीछे नहीं हटेगी। हुआवे कुछ अर्थों में चीनी राष्ट्रवाद के प्रतीकों में से एक मानी जाती है। इसे 'चीन के उभार' की एक अहम कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में इस कंपनी पर किया गया कोई भी हमला चीन खुद पर एक हमला मानता है। इसके अलावा अमेरिका ने हुआवे की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझू के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपने पत्ते भी अभी तक नहीं खोले हैं जिन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में कनाडा से गिरफ्तार किया गया था।

अमेरिका और चीन के बीच यह संघर्ष केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही नहीं रह गया है। वाशिंगटन अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव डाल रहा है कि वे चीनी कंपनी को अपने मोबाइल नेटवर्क के काम से दूर रखें। कुछ देशों पर इसका असर भी हो रहा है। खासतौर से पश्चिम के देश हुआवे को लेकर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हाल में डच खुफिया सेवा भी जासूसी के मामले में हुआवे की जांच कर रही है। उसे संदेह है कि चीनी सरकार हुआवे के माध्यम से ग्राहकों के डाटा में सेंधमारी कर रही है। यह सब कुछ एक ऐसे समय में हो रहा है जब डच सरकार को नीदरलैंड में नए 5जी नेटवर्क के लिए हुआवे की भागीदारी पर विचार करना है। ब्रिटेन में भी दूरसंचार सेवा प्रदाता बीटी ने गत वर्ष पुष्टि की थी कि वह अपने 4जी नेटवर्क के प्रमुख इलाकों से हुआवे के उपकरण हटा रही है। खुफिया एजेंसी एमआइ6 द्वारा जताई चिंताओं के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान पहले ही हुआवे के 5जी उपकरणों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूरोप के अधिकांश देश भी चीन की इस तकनीकी दिग्गज के साथ अपने संबंधों की नए सिरे से समीक्षा में जुटे हैं।

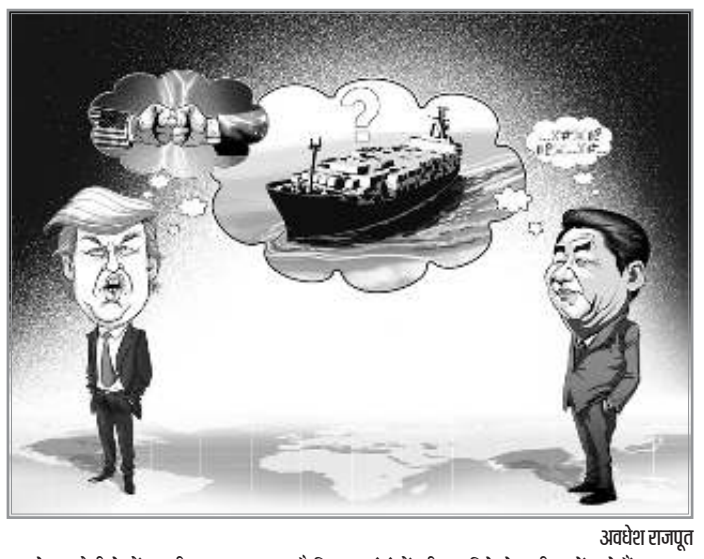

अवधेश राजपूत

कुल मिलाकर दांव बहुत ऊंचे लगे हैं, क्योंकि यह चीन और अमेरिका के बीच व्यापार और वैश्विक प्रभुत्व को लेकर चल रही खींचतान का हिस्सा है। कुछ हफ्तों पहले अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का कुछ समाधान निकलता दिख रहा था, लेकिन अब उसमें नए सिरे से तल्खी आ गई है। इसमें अमेरिका ने दबाव बढ़ाते हुए बीते हफ्ते चीन के 200 अरब डॉलर के चीनी आयात पर शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया। चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के 60 अरब डॉलर के उत्पादों पर आयात शुल्क की दरें बढ़ा दीं। इस साल की शुरुआत में ही दूरसंचार उपकरणों के मोर्चे पर हुआवे की बादशाहत कायम होते देख ट्रंप प्रशासन ने कुछ कदम उठाए थे जिनसे अमेरिका में नए वायरलेस नेटवर्क का जाल बिछाने के काम को गति दी जाए। इसमें आह्वान किया गया कि 5जी की होड़ अमेरिका को हर हाल में जीतनी चाहिए। मगर यह अभी तक स्पष्ट नहीं कि हुआवे के वर्चस्व की काट के लिए कोई कारगर रणनीति बनाई भी गई या नहीं, क्योंकि अमेरिका में हुआवे की टक्कर का कोई भी 5जी नेटवर्क आपूर्तिकर्ता नहीं है। इस मामले में चीन के प्रयास बहुत सधे हुए हैं और वह दशकों से तकनीकी मोर्चे पर छलांग को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर लेता आया है। तकनीकी क्रांति के अगले चरण में खेल का पासा पलटने की क्षमता वाली अपनी भूमिका को देखते हुए 5जी वैश्विक तकनीकी जगत का नेतृत्व करने की चीनी आकांक्षाओं की धुरी बनती हुई दिख रही है। हुआवे के इतिहास और चीनी कानूनों के चलते पश्चिमी देशों की राजधानियों में इस चीनी दिग्गज के उभार को लेकर घबराहट का भाव बढ़ा है। असल में चीन के कानून ऐसे हैं जिसमें अगर सरकार को कोई खुफिया जानकारी चाहिए तो इसमें घरेलू कंपनी को उसकी मदद करनी होती है।

भारत में भी अगले महीने से 5जी का बहुप्रतीक्षित ट्रायल शुरू होना है। हुआवे के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों को देखते हुए इसे लेकर अभी भी कुछ हिचक स्वाभाविक है। परीक्षण के लिए अभी तक किसी भी सेवा प्रदाता ने हुआवे को साझेदार नहीं बनाया है। इस मामले में अभी फैसला किया जाना शेष है। शायद वह पहले दौर के परीक्षणों का हिस्सा न भी बने, लेकिन यह मामला अभी विचाराधीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि हमेशा एक कड़ी से जुड़ी होती हैं, लेकिन व्यापार एवं तकनीकी टकराव में अमेरिका और चीन जैसे देशों में जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसमें भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक गुंजाइश लगातार सिकुड़ती जाएगी। ऐसे में नई दिल्ली को दीर्घावधिक दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे न केवल तात्कालिक हित सुरक्षित रहें, बल्कि उसकी स्वयं की तकनीकी क्षमताओं को भी बल मिले।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

मूर्तिभंजन के बाद याद आए ईश्वरचंद्र

राजीव सचान

ईश्वरचंद्र विद्यासागर सरीखे मनीषियों के साथ योद्धाओं की एक लंबी कतार है जिनसे देश अपरिचित-अनजान सा है

कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान विद्यासागर कॉलेज में समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने पश्चिम बंगाल ही नहीं सारे देश का ध्यान खींचा। जहां पश्चिम बंगाल में यह प्रतिमा भंजन चुनावी मुद्दा बन गया वहीं शेष देश में तमाम लोग इस सवाल से दो-चार होते दिखे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे कौन? सोशल मीडिया में ऐसी टिप्पणियां देखने को मिलीं जिनसे यह आभास हुआ कि कई लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित ही नहीं। उम्मीद की जाती है कि इनमें से बहुत से लोगों ने यह जानने की कोशिश की होगी कि आखिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान क्या है? यह सही है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक शिक्षाविद् और समाज सुधारक के तौर पर बंगाल में अधिक छाप छोड़ी, लेकिन वह इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके नाम-काम से सारे देश को परिचित होना चाहिए। उनका योगदान केवल इतना ही नहीं है कि उन्होंने विधवा विवाह की मुहिम छेड़ी और अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करके एक मिसाल कायम की। उन्होंने बांग्ला भाषा के व्याकरण को दुरुस्त करने के साथ इस धारणा को दूर करने का काम किया कि केवल ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने विद्यालय में वह नियम बदला जो यह कहता था कि केवल ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी हैं। संस्कृत का विद्वान होने के बावजूद उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों को खत्म करने का काम किया। इसी के तहत उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की जरूरत पर बल दिया और कम उम्र में उनके विवाह की प्रथा का विरोध किया। उन्होंने खास तौर पर लड़कियों के लिए कई स्कूल स्थापित किए। यही मुहिम आगे चलकर विधवा विवाह के चलन का कारण बनी। जिस विद्यासागर कॉलेज में उनकी प्रतिमा खंडित हुई वह भी उन्होंने 1872 में स्थापित किया था। यह देश का पहला ऐसा कॉलेज था जिसे भारतीयों ने अपने बलबूते शुरू किया था। वास्तव में इसी कारण उन्हें समय से आगे की सोच रखने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या यह एक विडंबना नहीं कि यह हम तब जान रहे हैं जब उनकी प्रतिमा टूटी?

ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक मात्र ऐसी हस्ती नहीं जिनके बारे में आज की पीढ़ी ज्यादा नहीं जानती या फिर न के बराबर जानती है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सरीखे समाज सुधारकों, मनीषियों के साथ योद्धाओं की एक लंबी कतार है जिनसे देश अपरिचित-अनजान सा है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें इतिहास में भी ढंग से जगह नहीं मिली। निःसंदेह कुछ ऐसे हैं जो प्रतिमाओं में कैद हैं या फिर जिनके नाम से रास्ते-चौराहे

और भवन आदि हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि आज की पीढ़ी उनके बारे में अच्छे से जानती है। कई हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके नाम-काम से पुरानी पीढ़ी तो परिचित है, लेकिन नई पीढ़ी अपरिचित। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि इसके आसार न के बराबर हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऐसी ही अन्य अनेक हस्तियों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। यह अंदेशा इसलिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा के तहत महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ाई को अब जरूरी नहीं समझा जाता। रही-सही कसर इतिहास के एकांगी स्वरूप ने पूरी कर दी है। इस मान्यता में एक बड़ी हद तक सच्चाई है कि भारत का इतिहास वस्तुतः दिल्ली के शासकों का इतिहास है। दिल्ली या फिर उसके आसपास किस शासक ने कब शासन किया, यह तो खूब पढ़ाया जाता है, लेकिन शेष भारत के शासकों के बारे में क्षेत्र विशेष के लोग ही परिचित हैं और वह भी थोड़ा-बहुत। दक्षिण और पूर्वी भारत के शासकों की विजय गाथाओं से पूरा देश परिचित नहीं, जबकि ये दक्षिण के ही शासक थे जिनके कारण हिंदू संस्कृति पूर्वी एशियाई देशों कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि तक पहुंची।

निःसंदेह ऐसा नहीं है कि हम केवल प्राचीन इतिहास से ही अपरिचित हैं। हाल का इतिहास भी हमसे ओझल है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगाल की बेहद ताकतवर सेना को हराया था। इस तरह किसी एशियाई राजा ने पहली बार किसी यूरोपीय सेना को हराया था, लेकिन इतिहास की हमारी किताबें शायद ही इस शासक के बारे में विस्तार से कुछ बताती हों। इतिहास की किताबें यही ज्यादा बताती हैं कि हमारे योद्धाओं ने जो भी बड़ा युद्ध लड़ा उसमें वे पराजित हुए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमें उन युद्धों के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया कि जिनमें हमारे योद्धाओं ने जीत हासिल की।

इन दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चर्चा में है। इस पार्टी के बड़बोले नेता और मंत्री ओमप्रकाश राजभर को बीते दिनों बर्खास्त कर दिया गया। पता नहीं अब वह क्या करेंगे, लेकिन क्या औसत भारतीय तो दूर रहे, उत्तर प्रदेश के औसत लोग भी सुहेलदेव के पराक्रम से भली तरह परिचित हैं? 11वीं सदी में श्रावस्ती के शासक रहे सुहेलदेव ने महमूद गजनी के भतीजे को मार गिराने के साथ उसकी सेना को बुरी तरह हराया था। कहते हैं कि इसके बाद वर्षों तक किसी विदेशी आक्रमणकारी ने इस इलाके की ओर रुख नहीं किया। अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी न बनती तो शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी यह न जानते कि जिस हस्ती के नाम पर यह पार्टी बनी उन्होंने क्या करिश्मा कर दिखाया था? वास्तव में ऐसे बहुत से नाम हैं जो इतिहास में दफन से हैं और फिर भी जब कभी यह मांग होती है कि इतिहास को सही रूप में चित्रित किया जाए तो यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि उसका भगवाकरण किया जा रहा है। बीते दिनों ही राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि इतिहास की किताबों में अब यह पढ़ाया जाएगा कि न अकबर महान थे और न ही राणा प्रताप। आखिर यह इतिहास की लीपापोती नहीं तो क्या है? इतिहास यानी 'ऐसा ही हुआ' था। साफ है कि जरूरत केवल इसकी नहीं कि इतिहास को सही रूप में सामने रखा जाए, बल्कि इसकी भी है कि इतिहास के भूले-बिसरे नायकों को देश से परिचित किया जाए। क्या यह विचित्र नहीं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा उनके नाम वाले शिक्षा संस्थान में एक ऐसे कमरे में रखी थी जहां सभी छात्रों के लिए जाना संभव नहीं था। पता नहीं उनकी प्रतिमा को किसने तोड़ा, लेकिन जरूरी केवल यह नहीं कि दोषी लोगों की पहचान कर उन्हें दंड का पात्र बनाया जाए, बल्कि यह भी है कि उनके जैसे समाज सुधारक आज की पीढ़ी से अपरिचित से न रहें। आखिर इससे खराब बात और क्या हो सकती है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ दिए जाने के बाद देश उनसे परिचित हो?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर दर्शन

ईश्वर और ब्रह्म पर्यायवाची हैं। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ही का रूप है। इस प्रकार ईश तत्व ब्रह्मांड के जड़ चेतन के कण-कण में समाया हुआ है। ईश्वर अनादि और इच्छारहित होकर ब्रह्मांड का स्वामी है जिसे केवल तार्किक बुद्धि द्वारा नहीं मापा जा सकता है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां-आंख, कान, नाक तथा त्वचा आदि उसी को देख या सुन सकती हैं जो प्रकृति तत्वों-आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि से निर्मित होते हैं, परंतु ईश्वर निराकार है तथा वह इन तत्वों से अलग है। ईश्वर के इस विशाल स्वरूप को मनुष्य केवल मन के भाव से ही अनुभव कर सकता है। नास्तिकों में ईश्वर को जानने की भावना ही नहीं होती, इसलिए नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं, जबकि विश्व के हर धार्मिक समुदाय ने ईश्वर को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है।

ईश्वर को अनुभव करने की भावना के लिए सनातन धर्म में अध्यात्म का मार्ग बताया गया है। अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा और विश्वास जरूरी है जिनसे मनुष्य मन के विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ एवं मोह का त्याग करके वैराग्य की अवस्था में जाकर मन को निर्मल बनाकर उसमें ईश तत्व का प्रवेश कराता है। इस अवस्था को ज्ञान की अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना उस परम चेतना से जुड़ जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और मनुष्य ईश्वरीय चेतना में स्थित परम शांति को अनुभव करते हुए परमानंद का अनुभव करता हुआ अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है।

ईश तत्व हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है, परंतु मन के विकारों के आवरण में ईश तत्व रूपी आत्मा छुपी रहती है। यदि वैराग्य के द्वारा मन के आवरण को हटा दिया जाए तो ईश तत्व रूपी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं जिसे आत्म-साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक रूपी अस्त्र है जिससे वह आत्म-साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य मानव जीवन का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिए नहीं करता है वह वास्तव में अपने विनाश के मार्ग पर चल रहा है और वह वाकई अभागा है। मानव जीवन का मर्म समझने के लिए आत्ममंथन अपरिहार्य है।

कर्नल (रिटायर्ड) शिवदान सिंह

शिक्षा में मिड-डे मील की भूमिका

सुधीर कुमार

सामाजिक-आर्थिक समानता को समाज में पुन: स्थापित करने में मिड-डे मील योजना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है

देश में नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य एवं साक्षरता के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना को एक सफल योजना के तौर पर देखा जाता है। इससे ग्रामीण भारत के सामाजिक बदलाव पर सकारात्मक असर पड़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मिड-डे मील के माध्यम से देश के 10.80 करोड़ बच्चों को फायदा हुआ है। जाहिर है अगर यह योजना शुरू नहीं की गई होती तो इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम ही रह जाते। इससे उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाते!

मिड-डे-मील योजना ने शिक्षा जगत में कई क्रांतिकारी परिवर्तनों की आधारशिला रखी है। सामाजिक-आर्थिक समानता को समाज में पुनः स्थापित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भले ही देश का शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) 6-14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करता है, लेकिन गरीबी और बेकारी की गिरफ्त में जकड़े परिवार को इतना सोचने का वक्त कहां? कहीं-न-कहीं ये विपरीत परिस्थितियां ही बालश्रम एवं अशिक्षा जैसी कुरीतियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। लेकिन मध्याह्न भोजन योजना के प्राथमिक विद्यालयों में लागू होने के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अब थाली लेकर ही सही बच्चे विद्यालय पहुंचने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए सुखद है, क्योंकि अब बच्चे उन अभिशप्त परिस्थितियों से मुक्ति तो पा रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने बचपन को दांव पर लगाने को विवश होना पड़ता था। विद्यालय में उपस्थित रहने से कुछ शब्द तो उनके कान में पड़ ही जाते हैं। साथ ही प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए बच्चा अभ्यस्त तो हो रहा होता है। नियमित विद्यालय जाने से बच्चे न सिर्फ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि अनुशासन, खेल, सहयोग एवं सम्मान की भावना तथा नेतृत्व के गुण भी सीख रहे हैं। व्यक्तिगत विकास के अलावा बच्चे सामाजिक तौर पर भी परिपक्व हो रहे हैं। छोटी उम्र से ही ये बच्चे धर्म, जाति, संप्रदाय एवं परिवार आदि में विभेद किए बिना एक साथ भोजन कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। इससे आने वाले समय में देश में सामाजिक-आर्थिक भेदभाव तथा असमानता की दीवारें निश्चित तौर पर टूटेंगी!

मध्याह्न भोजन योजना अपने आप में एक अनोखी योजना है। भारत में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की कुल तादाद के 79 फीसद बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना बहुत हद तक सफल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिड-डे मील योजना ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बहुआयामी है। मिड-डे मील से जुड़ी अनियमितता पर रोक लगाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्था में सुधार की जाए तथा इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी भरोसेमंद लोगों को सौंपी जाए तो तस्वीर बदलती देर नहीं लगेगी!

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

राष्ट्र-नायक वीर सावरकर

हृदयनारायण दीक्षित ने अपने आलेख इतिहास से अनावश्यक छेड़छाड़ में जिस कांग्रेसी मानसिकता को उद्घाटित किया है, वह उसकी सुविधाजनक राजनीति का एक हिस्सा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार स्कूली पाठ्य पुस्तकों में दर्ज इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए राष्ट्र-नायक वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला एक कायर क्रांतिकारी बताकर बच्चों के कोमल मस्तिष्क में वीर सावरकर की गलत तस्वीर उभारने का प्रयास कर रही है। वैसे भी भारत के मान बिंदुओं की छवि को धूमिल कर आक्रांता मुगलिया शासकों की शान में कशीदे काढ़ना कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। इसमें वामपंथी इतिहासकारों की भी भूमिका रही है, जिन्होंने कांग्रेस के इस अभारतीय भाव को उभारने का काम किया है। इतिहास की सत्यता को विकृत करते हुए उसे तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना एक अपराध है, जिसे कांग्रेसी शासन में वामपंथियों द्वारा बार-बार दोहराया गया, लेकिन अब समय की मांग है कि भारत के इतिहास को उसके मूल सत्य के साथ प्रस्तुत किया जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनके अतुलनीय साहस और धीरता के लिए याद किया जाए न कि एक 'क्षमा-याचक' के रूप में। वीर सावरकर जैसे महापुरुष को 'क्षमा-याचक' बनाना वामपंथी रस में पगा हुआ कांग्रेसी षड्यंत्र है, जिससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वीर सावरकर हर भारतीय के मन में बसे हुए एक ऐसे बलिदानी राष्ट्र नायक हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

pandeyvp1960@gmail.com

अल्पमत है क्षेत्रीय दलों की कामना

कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की सांसें अटकी हुई हैं। सबसे अधिक उत्तेजना एनडीए के घटक दलों में है। वे चाहते हैं कि भाजपा अपने बूते पूर्ण बहुमत से दूर रहे, इसी में उनकी भलाई है। जाहिर है यदि भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है तो वे भाजपानीत सरकार से अपने अनुसार मोलभाव नहीं कर सकेंगे। यदि भाजपा बहुमत से कम रहती है तो घटक दलों की बांछे खिलनी तय हैं, क्योंकि सरकार में रहकर या उससे बाहर रहकर भी ये उनसे अपनी मांगें मनवा सकते हैं। बहुमत से कम संख्याबल रहने पर एनडीए से इतर कुछ अन्य छोटे दल भी संभावित सरकार से अनुनय-विनय करवाने और मोलभाव करने की स्थिति में रहना चाहेंगे। पिछली सरकार में जैसे चंद्रबाबू नायडू आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद दबाव बनाए हुए थे, ठीक उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रभावशाली ढंग से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अगली बनने वाली सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसी प्रकार शिवसेना मराठी अस्मिता के नाम पर सरकार को नाकों चने चबवाने और महाराष्ट्र में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के लिए प्रदेश में बड़े भाई की स्थिति में रहना पसंद करेगी। लोकजनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी मनमुताबिक स्थिति के लिए मोलभाव करने में पीछे नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह है कि अल्पमत की सरकार तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए खांड की बोरी से कतई कम नहीं। ये इसी